(i) (ग) और (घ) उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण में दिए गए है ।

**विवरण**

मध्य प्रदेश विधुत बोर्ड के विधुत स्टेशनों की विधुत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम ।

1. **ताप विधुत स्टेशन**

संजय गांधी ताप विधुत स्टेशन में प्रत्येक 210 मे0 वा0 वाली यूनिट 3 एवं 4 का निर्माण कार्य एम पी ई बी किया जा रहा है । यूनिट 3 और 4 को चालू करने का निर्धारित कार्यक्रम क्रमश : जून 99 और दिसम्बर 99 है;

वर्तमान में कोरवा पूर्वी टी पी एस का चरण-11 (4x50 मे0 वा0) की ह्रासित क्षमता पर कार्य कर रहा है और अमरकंटक टी पी एस में चरण – 1 की एक 30 मे0वा0 वाली यूनिट 20 मे0 वा0 की ह्रासित क्षमता पर कार्य कर रही है; यूनिटों की मूल क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए इन ताप विधुत स्टेशनों में नवीकरण कार्य किया जा रहा है उपरोक्त के अतिरिक्त यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरनी, कोरवा पश्चिम, कोरवा पूर्व तथा अमरकंटक टीपीएस में भी नवीकरण और आधुनिकीरण कार्य किया जा रहा है ।

2. **जल विधुत स्टेशन्स**

राजघाट जल विधुत परियोजना 3x15 का बाणसागर जल विधुत परियोजना 2x15 मे0वा0 चरण-II, 3X20 मे0 वा0 चरण-II , 2X10 मे0 वा0 चरण IV का निर्माण कार्य एम एस ई बी द्वारा किया जा रहा है । इन यूनिटों को चालु करने की निर्धारित तिथियां नीचे दी गई है:-

1. बाणसागर जल विधुत परियोजना इन विधुत स्टेशन चरण-II (2) X 15 मे0 वा0) को चालू करने
(1) जुलाई 2000 का कार्यक्रम
(2) अक्टूबर 2000 अंतिम है और

बाणसागर एच ई पी चरण-II 3X20 मे0 वा0)बांध के शीर्ष पर

(1) यूनिट-I जुलाई 99 तक निर्माण पर
(2) यूनिट-II अक्टूबर 99 जाने और निधियों
(3) यूनिट-III फरवरी 2000 उपलब्धता पर आधारित है

(3) बाणसागर एचईपी चरण-IV 2X20 मे0 वा0)
(1) जुलाई 2002
(2) अक्टूबर 2002

(4) राजघाट एच ई पी (3X15 मे0 वा0 )

(1) यूनिट-I जुलाई 1998(अंतिम)
(2) यूनिट-II सितम्बर 1998
(3) यूनिट-III नवम्बर 1998

**Power projects in Uttar Pradesh**

577. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of power projects received from the public and private sector during the last two years in Uttar Pradesh and which of them are still pending; and

(b) by when these are proposed to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE ON THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The details of proposals received from the Public and Private Sector during the last 2 years for selling up of power projects in Uttar Pradesh as on June, 1997 arc as follows:

| SI. No, | Name of the Project | Sector | Capacity | Status of clearances |
|---|---|---|---|---|
| 1.2, | Vishnupruyug HEP Dhauliganga (Intermediate Stage) | Private NHPC | 400, MW 210 MW | CEA cleared, DPR under examination in CEA, |

| SI. No. | Name of the Project | Sector | Capacity | Status of clearances |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Jawaharnagar TPP | Private | 800 MW | Returned' a*, inputs, like fuel linkage, water availability, etc., not tied. up. |
| 4. | Srinnagar HEP | Private | 330 MW | Returned as inputs were not tied up. |
| 5. | Rosa TPP | Private | 567 MW | Scheme under examination. |

Techno-cconomic clearance for the schemes 2 to 5 will be subject to the appraisal by CEA and tying up of necessary inputs/linkages by the project authorities.

**Investment made in the power sector**

578. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the total amount of investment made in power sector during 8th Plan period;

(b) whether Government propose to step up investment in the power sector during 9th plan;

(c) if so, the fund earmarked therefor; and

(d) the state-wise details of the investment proposed to be made in that plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K.' ALAGH): (a) The likely expenditure in the Eighth Plan in Public Sector is Rs. 76067.19 crores.

(b) to (d) The 9th five Year Plan (1997-2002) is still under finalisation in the Planning Commission. It has, however, been decided that the power sector will be funded on a priority basis.

**राज्य विधुत बोर्डो में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कदम**

579. **श्री नागमणि** : क्या **विधुत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि राज्य विधुत बोर्डो को अधिक प्रभावी बनाने एवं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कोई समिति बनाई गई है**;**

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राज्य विधुत बोर्डो को असफल घोषित करके इस कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है**;** और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**विज्ञान और प्रौधोगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधुत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ)** : (क) जी, नही । तथापि, भारत सरकार ने 16.10.76 तथा 3.12.86 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सम्मति के आधार पर विधुत हेतु एक समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना (सी0एम0एन0पी0पी0) का गठन करके उसके क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को परिपत्रित कर दिया है । इस कार्य योजना में राज्य बिजली बोर्डो को स्वायत्तता, प्रबंधन पद्धतियों तथा रा0वि0ओ0 के भौतिक मानदण्डों में सुधार हेतु प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा अधिक सुस्पष्ट प्रणालियों को अपनाया जा सके जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।